>

Title: Regarding preparation of National BPL list.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आजादी के 64 साल बीत गए। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों का आंकलन आज तक नहीं हो पाया है। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमान लगाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए।

महोदय, सादर अनुरोध है कि बिहार में बीपीएल परिवारों का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील और गम्भीर रहा है। सच्चाई यह है कि राज्य सरकार द्वारा कराए गए अनुसंधान और सर्वेक्षण से बीपीएल परिवारों का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख का है।

जबकि केन्द्र सरकार ने सिर्फ 65 लाख बीपीएल परिवार को ही निर्धारित किया है जोकि बिल्कुल विरोधाभासी है। इन आंकड़ों के असंगत होने से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहा गरीबी उपशमन कार्यक्रम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसका दुखद पहलू यह है कि इससे प्रदेश की अशिक्षित और गरीब जनता बुरी तरह से प्रभावित होती है। तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट द्वारा सीमा तय किये जाने के बाद बीपीएल श्रेणी से जुड़े लाभों को पात्र जनता को दे पाना संभव नहीं हो पाता है। एक सच यह भी है कि अन्य राज्य बीपीएल का लाभ उठाने के लिए बेमेल और गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। बेहतर यह होगा कि निर्वाचन आयोग की भांति एक स्वतंत्र बीपीएल आयोग का गठन किया जाए।

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कहा है कि सही मापदंड नहीं अपनाए जाने से समाज में आर्थिक विपन्नता और पिछड़ेपन का नया चेहरा सामने आयेगा, जो राष्ट्र और समाज के लिए बेहद खतरनाक होगा।